नईदुनिया

संपादकीय

दिल्ली में आप का इम्तिहान

इलेक्शन कमिशन की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित किए जाने से राष्ट्रीय राजधानी में सियासी जंग का विधिवत शंखनाद हो गया है। हालांकि अघोषित तौर पर यह लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। तीनों प्रमुख पार्टियां न केवल प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं बल्कि आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी का सिलसिला भी उसी रूप में चला रही हैं मानो चुनाव प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया हो।

दिल्ली की यह चुनावी लड़ाई इस मायने में खास नहीं कही जाएगी कि इस बार भी वही तीनों दल प्रमुखता से मैदान में हैं, जो पिछले चुनावों में थे। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से यहां तिकोना मुकाबला ही हो रहा है। यह अलग बात है कि इस अपेक्षाकृत नई पार्टी ने एक बार वर्चस्व स्थापित होने के बाद यहां अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी। पिछले दो चुनावों में उसे दिल्ली की जनता से शानदार बहुमत मिला। नई और दो राज्यों में सत्तारूढ़ होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने आक्रामक शैली की राजनीति से अपनी अलग पहचान बनाई है। इस आक्रामकता ने जहां आम आदमी पार्टी को नई धार दी है, वहीं अन्य दलों के साथ उसके संबंधों को भी सहज-सामान्य होने से रोका है। शायद यही वजह है कि बीजेपी तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत से लगी ही हुई है, कांग्रेस भी उस पर हमले करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। इसमें खास बात सिर्फ यही है कि छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों ही विपक्षी दलों के आईएनडीआईए ब्लॉक में शामिल थे और बीजेपी पर संयुक्त हमला कर रहे थे। जाहिर है, इनके बीच की तीखी बयानबाजी आईएनडीआईए ब्लॉक के अंदर असहजता पैदा कर रही है और शिवसेना जैसे दल इनसे संयम बरतने की अपील भी कर चुके हैं।

जिस तरह से यह चुनाव लड़ा जा रहा है, उससे साफ है कि नतीजा चाहे जो भी हो उसके निहितार्थ दूर तक जाएंगे। दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के आंतरिक समीकरण के लिहाज से भी अहम है। ऐसे में वह हर हाल में अपनी कामयाबी दोहराना चाहेगी। इस बीच, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आईएनडीआईए ब्लॉक के आंतरिक समीकरणों में किस तरह के बदलाव आते हैं।

महाकुम्भ मेले का आध्यात्मिक एवं आर्थिक महत्व

प्रहलाद सबनानी

हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार कुंभ मेला एक धार्मिक महाआयोजन है जो 12 वर्षों के दौरान चार बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में चार स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल चार पवित्र नदियों पर स्थित चार तीर्थस्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है, यथा, (1) हरिद्वार, उत्तराखंड में, गंगा के तट पर; (2) मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर; (3) नासिक, महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर; एवं (4) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। प्रत्येक स्थल का उत्सव, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक-सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है।

कुम्भ मूल शब्द कुम्भक (अमृत का पवित्र घड़ा) से आया है। ऋग्वेद में कुम्भ और उससे जुड़े स्नान अष्ठान का उल्लेख है। इसमें इस अवधि के दौरान संगम में स्नान करने से लाभ, नकारात्मक प्रभावों के उन्मूलन तथा मन और आत्मा के कायाकल्प की बात कही गई है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी कुम्भ के लिए प्रार्थना लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन से निकले अमृत के पवित्र घड़े (कुम्भ) को लेकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर कुम्भ को लालची राक्षसों के चंगुल से छुड़ाया था। जब वह इस स्वर्ग की ओर लेकर भागे तो अमृत की कुछ बूंदे चार पवित्र स्थलों पर गिरीं जिन्हें हम आज हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इन्हीं चार स्थलों पर प्रत्येक तीन वर्ष पर बारी बारी से कुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है।

कुम्भ मेला दुनिया में कहीं भी होने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। मुख्य रूप से इस समागन में तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं, संन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं, अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं; हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है, शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में, तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां, जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं।

महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी, 2025 से 26 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। यह एक हिंदू त्यौहार है, जो मानवता का एक स्थान पर एकत्र होना भी है। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले में दुनिया भर से 15 करोड़ पर्यटक आए थे। यह संख्या 100 देशों की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। यह वास्तव में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध है। कुंभ मेला कई शताब्दियों से मनाया जाता है। प्रयागराज कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख वर्ष 1600 ई. में मिलता है और अन्य स्थानों पर, कुंभ मेला 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आयोजित किया गया था। कुंभ मेला बेहद पवित्र और धार्मिक मेला है और भारत के साधुओं और संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। वे वास्तव में पवित्र नदी के जल में स्नान करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। अन्य लोग इन साधुओं के शाही स्नान के बाद ही नदी में स्नान कर सकते हैं। वे अखाड़ों से संबंधित हैं और कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में आते हैं। घाटों की ओर जाते समय जब वे भजन, प्रार्थना और मंत्र गाते हैं, तो उनका जुलूस देखने लायक होता है।

कुंभ मेला प्रयागराज 2025 पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, जो 13 जनवरी 2025 को है और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। यह पर्यटकों के लिए भी जीवन में एक बार आने वाला अनुभव है। टेंट और कैंप में रहना आपको एक गर्मजोशी भरा एहसास देता है और रात में तारों से भरे आसमान को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। कुंभ मेले में सत्संग, प्रार्थना, आध्यात्मिक व्याख्यान, लंगर भोजन का आनंद सभी उठा सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025 में गंगा नदी में पवित्र स्नान, नागा साधु और उनके अखाड़े से मिलें। बेशक, यह कुंभ मेले का नंबर एक आकर्षण है। कुंभ मेले के दौरान अन्य आकर्षण प्रयागराज में घूमने लायक जगहें हैं जैसे संगम, हनुमान मंदिर, प्रयागराज किला, अक्षयवट और कई अन्य। वाराणसी भी प्रयागराज के करीब है और हर पर्यटक के यात्रा कार्यक्रम में वाराणसी जाना भी शामिल है।

महाकुम्भ 2025 में आयोजित होने वाले कुछ मुख्य स्नान पर्व निम्न प्रकार हैं -

मुख्य स्नान पर्व 13.01.2025
मकर संक्रान्ति 14.01.2025
मौनी अमावस्या 29.01.2025
बसंत पंचमी 03.02.2025
माघी पूर्णिमा 12.02.2025
महाशिवरात्रि 26.02.2025

प्रयागराज का अपना एक एतिहासिक महत्व रहा है। 600 ईसा पूर्व में एक राज्य था और वर्तमान प्रयागराज जिला भी इस राज्य का एक हिस्सा था। उस राज्य को वत्स के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जिसके अवशेष आज भी प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गौतम बुद्ध ने भी अपनी तीन यात्राओं से इस शहर को सम्मानित किया था। इसके बाद, यह क्षेत्र मौर्य शासन के अधीन आ गया और कौशाम्बी को सम्राट अशोक के एक प्रांत का मुख्यालय बनाया गया। उनके निर्देश पर कौशाम्बी में दो अखंड स्तम्भ बनाए गए जिनमें से एक को बाद में प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रयागराज राजनीति और शिक्षा का केंद्र रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इस शहर ने देश को तीन प्रधानमंत्रियों सहित कई राजनौतिक हस्तियां दी हैं। यह शहर साहित्य और कला के केंद्र के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र रहा है।

भारत के उत्थान की प्रेरणा है राष्ट्र मंदिर

(श्रीराम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर विशेष)

हितानंद शर्मा

अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय वह अभिजीत मुहूर्त, जब प्राण-प्रतिष्ठा कर रामलला के नेत्रों से पट्टिका हटाई गई तो पूरे विश्व के सनातन संस्कृति के उपासकों के नेत्रों में श्रद्धा, आस्था, आनंद और प्रतीक्षा के आँसू थे। पौष शुक्ल द्वादशी, 22 जनवरी 2024 केवल अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के उत्सव का दिवस नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज की दृष्टि और विचारों के परिवर्तन की उपलब्धि का दिन है। पीढ़ियों की तपस्या, त्याग, बलिदान और प्रतीक्षा के बाद अयोध्या ने इस शुभ घड़ी का स्वागत किया था।

भगवान श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा से आनंदित, उत्साहित यह वही अयोध्या है जिसके परिचय में अथर्व वेद में उल्लेख आता है कि -

अष्ट चक्रा नव द्वारा देवाना पू. अयोध्यातस्या हिरण्यमयः कोश स्वर्गो 'योतिषावृतः । ।

अयोध्या, जिसका अर्थ ही है जो अजेय है, अपराजित है। सहस्त्रों वर्षो तक अयोध्या अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए जानी जाती रही। वही अयोध्या जहाँ हिन्दू समाज के आराध्य श्रीराम जी का जन्म सकल लोक के मंगल हेतु हुआ। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं-

विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।
निज इच्छा निर्मित प्रभु माया गुन गो पार ।।

हिन्दू समाज की आस्था के केंद्र, समरसता, नैतिकता व कर्तव्यपालन का बोध कराने वाले श्रीराममंदिर का कालांतर में विध्वंस कर मुगल आक्रांताओं द्वारा गुलामी के प्रतीक के रूप में बाबरी मस्जिद बना दी गई। इसके बाद 1528 से ही आरंभ हुए श्रीराममंदिर आंदोलन का 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय पर विराम हुआ। 5 अगस्त 2020 को भूमिपूजन के साथ करोड़ों लोगों की भावनाओं ने विविध प्रकार से उत्सव की अभिव्यक्ति की। यह एक ऐसा आंदोलन रहा जिसमें साधु-संतों ने युद्ध भी किया और वे आध्यात्मिक जागरण के केंद्र भी बने। बैरागी अभिराम दास (योद्धा साधु), राममंदिर आंदोलन के शलाका पुरुष महंत रामचन्द्र परमहंस, महंत अवैद्यनाथ व देवरहा बाबा ने संपूर्ण आंदोलन को एक दिशा प्रदान की। कोठारी बन्धुओं के बलिदान को हिन्दू समाज भला कैसे विस्मृत कर सकता है? विष्णु डालमिया, अशोक सिंहल वे तेजपुंज हैं, जिन्होंने सनातन ऊर्जा को संग्रहीत कर इस पवित्र कार्य से जोड़ा।

मंदिर आंदोलन के मूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका से सभी भलीभांति परिचित ही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे आंदोलन में जनजागरण करते हुए आस्था के उच्चतम प्रतिमानों को विश्वव्यापी स्वरूप दिया। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित विचार परिवार के सभी संगठनों ने अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस की मंशा के अनुरूप धैर्यपूर्वक योजनाबद्ध आंदोलन किए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में देशव्यापी रथयात्रा ने पूरे भारत में वातावरण का निर्माण किया तो असंख्य कारसेवकों के बलिदान ने राम राष्ट्र के इस यज्ञ में समिधा का कार्य किया।

मंदिर आंदोलन के इतिहास में अनेक बलिदानियों के रक्त व उनके परिजनों के त्याग का बिंदु समाहित है। राममंदिर के प्रति समाज की आस्था इतनी प्रबल रही है कि जब श्रमदान आवश्यक था तब श्रमदान किया। वहीं राष्ट्रमंदिर को भव्यता और दिव्यता देने के लिए निधि समर्पण अभियान में जाति, वर्ग, दल, समूह के सभी बंधनों को ध्वस्त करते हुए जिससे जो बन पड़ा उसने भगवान श्रीराम के चरणों में समर्पण किया ।

भारतीय पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी के आज ही के दिन जो पिछले वर्ष 22 जनवरी 2024 को पड़ी थी, भगवान के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा हुई थी। संपूर्ण भारत की आस्था के केंद्र श्रीराम मन्दिर के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना को बल मिला और देशवासियों में स्वाभिमान का जागरण हुआ। वहीं जो लोग मन्दिर निर्माण का विरोध कर रहे थे उनके सारे अवरोधों का प्रति उत्तर भी इस एक वर्ष में मिला। प्राण-प्रतिष्ठा से आज प्रथम वर्षगांठ तक असंख्य दर्शनार्थियों ने न केवल रामलला के दर्शन किए बल्कि अयोध्या सहित आस-पास के क्षेत्र के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नागर शैली में निर्मित अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण श्रीराम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट व ऊंचाई 161 फीट है। भव्य तीन मंजिला मंदिर में 392 स्तंभ और 44 द्वार हैं। भूतल में प्रभु श्रीराम का मोहक बाल रूप तो प्रथम तल में श्रीराम दरबार का गर्भगृह है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना व कीर्तन मंडप है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी विराजित हैं। मंदिर के समीप ही पौराणिक काल का सीताकूप रहेगा। 732 मीटर लंबे व 14 मीटर चौड़े चहुंमुखी आयताकार परकोटे के चार कोनों पर भगवान सूर्य, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव का मंदिर बनेगा। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी व देवी अहिल्या के मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मिकी, महर्षि मंदिर प्रस्तावित हैं।

यह मात्र एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक है। एक स्वाभिमानी राष्ट्र अपने ऐसे ही प्रतीकों से ऊर्जा प्राप्त करता है। राम मंदिर भारत की चेतना का पर्याय है और इसका भी कि राम जन-जन की स्मृति में कितने गहरे रचे-बसे हैं। यह आधुनिक विश्व के इतिहास में पहली बार है, जब किसी समाज ने अपने प्रेरणा पुरुष के जन्मस्थान एवं उनके उपासना स्थल को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से न्यायपूर्वक छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। इसी कारण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने देश-विदेश में कोने-कोने में बसे भारतीयों को भाव विभोर कर दिया था ।

प्राण-प्रतिष्ठा भारत ही नहीं, विश्व इतिहास में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व का सबसे बड़ा आयोजन था। इस आयोजन को लेकर उमड़ा भावनाओं का ज्वार ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर दे रहा था कि राम मंदिर का निर्माण क्यों आवश्यक था और हिंदू समाज उसके लिए इतनी व्यग्रता से क्यों प्रतीक्षा कर रहा था? अच्छा होता कि यह प्रतीक्षा स्वतंत्रता के बाद ही पूरी हो जाती, किंतु संकीर्ण राजनीतिक कारणों और सेक्युलरिज्म की विजातीय-विकृत अवधारणा के चलते ऐसा नहीं हो सका। यह विडंबना ही रही कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की हिंदू समाज की सदियों पुरानी स्वाभाविक अभिलाषा की अनदेखी की गई।

जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का बैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिशप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद दलित होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। समय के साथ समाज का संकल्प भी दृढ़ होता गया और आज समस्त सृष्टि अयोध्या के वैभव को निहार रही है। यह धर्म नगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है।

संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों का भी अभिनंदन है।

एक दूरदृष्टि लेकर भारत के न भूतो न भविष्यति के स्वर्णिम अवसर को साकार करने में उनकी महती भूमिका रही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। अब भारत को भव्य बनाने के संकल्प को पूर्ण करने की बारी है और भगवान श्रीराम का मंदिर इसकी प्रबल प्रेरणा है। ऐसा होना निश्चित ही है क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा से समस्त दिशाओं से शुभ संकेत मिलना आरंभ हो ही चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों के साथ-

मोरे जिय भरोस दृढ सोई, मिलहि राम सगुन सुभ होई. शुभमस्तु।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के संगठन महामंत्री हैं।)

आजकल

सबसे कम विकास दर

अगले वित्तवर्ष के बजट की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे वक्त में विकास दर संबंधी ताजा आकलन सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्तवर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 फीसद रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके 6.6 फीसद पर रहने का अनुमान लगाया था। अगर एनएसओ का अनुमान सही साबित होता है, तो यह कोरोनाकाल के बाद सबसे कम विकास दर होगी।

हालांकि एनएसओ के अनुमान के मुताबिक चालू वित्तवर्ष की दूसरी छमाही में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर बढ़ेगी। मगर इससे अर्थव्यवस्था के दूसरे पक्षों पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में कई चीजें काफी असंतुलित चल रही हैं।

चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर छह फीसद से नीचे दर्ज हुई थी और उसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान काफी नीचे नजर आया था, तभी से विशेषज्ञ वृद्धि दर को लेकर चिंतित नजर आने लगे थे। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है, पर वही सुस्त रफ्तार में चल रहा है। निर्माण क्षेत्र में भी सुस्ती देखी जा रही है। दूसरी छमाही में भी इसके कमजोर रहने का अनुमान है।

हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोनाकाल के बाद जो बढ़ी वृद्धि दर दर्ज हुई थी, वह स्वाभाविक नहीं थी। एनएसओ के ताजा आकलन में अर्थव्यवस्था की स्वाभाविक वृद्धि दर दर्ज हुई है। मगर महंगाई का रुख अब भी नीचे की तरफ नहीं रहने वाला। इसके पांच फीसद से ऊपर रहने का अनुमान है। यानी रिजर्व बैंक के लिए रेपो दरों में कटौती का निर्णय करना दुविधा का विषय होगा। इसके अलावा, सरकार को राजस्व घाटा पाटने के लिए अपने खर्चों में कटौती करनी होगी।

सरकार की कोशिश है कि राजस्व घाटा 4.9 फीसद पर रोक कर रखा जाए। मगर इसके लिए सरकारी खर्चों में कटौती करनी होगी और उसका असर कई महत्त्वाकांक्षी योजनाओं पर पड़ेगा। फिर, आर्थिक वृद्धि दर में कमी का प्रभाव प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी पड़ेगा। पहले ही सरकार को इस मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डालर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत और विदेशी निवेशकों के धन निकासी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार छीजन बनी रहने से अपेक्षित निवेश आकर्षित नहीं हो पा रहा।

क्या शिक्षा का अधिकार ऐसे ही सार्थक होगा?

राकेश दुबे

यदि हमारे देश भारत के करीब आधे स्कूल कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा से वंचित हों, स्कूल बढ़ रहे हों और दाखिले कम हो रहे हों, साथ ही विद्यार्थियों का बीच में पढ़ाई छोड़ने का आंकड़ा बढ़ रहा हो, तो इसे एक बड़ी चुनौती माना जाना चाहिए। नि:संदेह, आर्थिक विकास हमारी प्राथमिकता होता है लेकिन यदि बुनियादी शिक्षा तमाम विसंगतियों से जूझ रही हो तो विकास की सार्थकता पर सवाल उठेंगे। सवाल खासकर वंचित समाज के बच्चों का है, जिनका बड़ा संघर्ष जीवन-यापन की प्राथमिकताओं से जुड़ा है।

स्वतंत्र भारत में शैक्षिक सुधार के जो प्रयास हुए,उनका लाभ वंचित समाज को काफी अधिक हुआ है। दरअसल, सरकारी स्कूल समाज के कमजोर वर्ग की आशा के केंद्र रहे हैं। यदि आज इन समाजों के बच्चे ही शिक्षा से दूर हो रहे हैं, तो तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश में आज भी लाखों बच्चे शिक्षा पाने से वंचित हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे खासे चौंकाने वाले हैं। समीक्ष्य वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि इससे पहले साल के मुकाबले स्कूल में दाखिलों में 37.5 लाख की कमी आई है। जहां वर्ष 2022-23 में स्कूलों में 25.17 करोड़ विद्यार्थी दर्ज थे, वहीं 2023-24 में यह संख्या घटकर 24.80 करोड़ हो गई है। यह आंकड़ा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर का है। वहीं, समीक्ष्य अवधि में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जिनमें छात्राएं, वंचित व कमजोर वर्ग के बच्चे अधिक हैं। ऐसे में मंथन की जरूरत है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के तमाम प्रयासों, नई शिक्षा नीति लागू होने, अधिक स्कूल खुलने के बावजूद छात्रों के दाखिले में कमी क्यों आ रही है। सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत के अंतर को संबोधित करने की जरूरत है। ताकि नये दाखिलों को प्रोत्साहन मिले और छात्र भी बीच में स्कूल न छोड़ें।

जरूरत इस बात की है कि जहां एक ओर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, वहीं स्कूलों में दाखिले को लेकर छात्रों का आकर्षण भी बना रहना चाहिए। साथ ही शिक्षा को व्यावहारिक बनाने और समय के साथ कदमताल करने की जरूरत है। वहीं, दूसरी शिक्षा मंत्रालय के प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के यह तथ्य चिंता बढ़ाने वाले हैं कि अभी तक कुल 57 प्रतिशत स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा मौजूद है। दूसरी ओर 53 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे दौर में जब ऑनलाइन पढ़ाई का खासा जोर है तो ये बच्चे भविष्य में निजी स्कूलों के छात्रों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उनका क्या भविष्य होगा?

विडंबना यह है कि वंचित समाज व कमजोर वर्ग के परिवारों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं, जिनके पास न तो कंप्यूटर है और न ही स्मार्ट फोन। दरअसल, उनके परिवारों के जीवन यापन का संघर्ष इतना बड़ा है कि कंप्यूटर व स्मार्ट फोन उनकी प्राथमिकता नहीं बन सकते। चिंता की बात यह है कि निम्न मध्यवर्गीय लोग तो निजी स्कूलों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं, लेकिन कमजोर वर्ग के विद्यार्थी कहां जाएंगे?

दरअसल, मौजूदा दौर में सिर्फ साक्षरता से खुश नहीं हुआ जा सकता, जरूरत गुणवत्ता की शिक्षा की भी है। ताकि स्कूल से निकलकर विद्यार्थी देश-दुनिया के साथ कदमताल कर सकें।

मंथन इस बात को लेकर भी होना चाहिए कि क्यों लाखों बच्चे स्कूलों की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर क्यों छात्र स्कूल में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई बीच में छोड़कर जा रहे हैं? शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब सामाजिक विसंगतियां दूर होंगी। यहां सवाल स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों के अनुपात का भी है। यह ठीक है कि स्कूलों के भवनों के स्तर में सुधार हुआ है, स्कूलों में बिजली, पानी व जेंडर अनुकूल शौचालय बने हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता केवल स्कूलों में संरचनात्मक विकास ही नहीं होना चाहिए, बल्कि शैक्षिक वातावरण भी बच्चों की पढ़ाई के अनुकूल होना चाहिए।